भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1688

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत प्राप्त प्रगति

1688. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025 में डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत देशभर में एग्रीस्टैक, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, किसान ई-मित्र और नमो ड्रोन दीदी सहित राज्यवार प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर तेलंगाना में पंजीकृत और प्रमाणित किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है और भू-अभिलेखों के साथ कितना एकीकरण हुआ है;

(ग) क्या आरंभ करने से पहले की तुलना में ऋण, फसल बीमा और वास्तविक समय परामर्श तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेलंगाना में विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों की अधिक आबादी वाले जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.): देश में वर्ष 2025 में डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत प्राप्त प्रगति, जिसमें एग्रीस्टैक, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, किसान ई-मित्र और नमो ड्रोन दीदी शामिल हैं, निम्नलिखित हैं:

I. एग्रीस्टैक: एग्रीस्टैक एक डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) है जिसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात् किसान रजिस्ट्री, जियो रेफेरेंस्ड् ग्राम मानचित्र और बोई गई फसल रजिस्ट्री। ये सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाए और अनुरक्षित किए जाते हैं। यह किसानों की पहचान, भूमि और उनकी फसलों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत स्थापित करता है।

किसान आईडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई),

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित खरीद, ऋण वितरण, इनपुट वितरण और आपदा राहत के सुचारू एकीकरण को सक्षम बनाती है। दिनांक 04.02.2026 तक, देश भर में 8.48 करोड़ से अधिक किसान आईडी जारी की जा चुकी हैं। तेलंगाना राज्य सहित संपूर्ण देश में जारी की गई किसान आईडी का विवरण अनुबंध में दिया गया है। तेलंगाना ने लघु एवं सीमांत किसानों सहित सभी श्रेणियों के किसानों को शामिल करने के लिए अपने कृषि विस्तार अधिकारियों (एईओ) की सेवाएं ली हैं। तेलंगाना ने किसान रजिस्ट्री में किसानों के नामांकन के लिए अपने मी (Mee) सेवा केंद्रों में यह सेवा प्रदान की है।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण ने फसलों की प्लॉट-लेवल विजिबिलिटी और विभिन्न सीजन में बुआई के पैटर्न का बेहतर अनुमान लगाने में सहायता की है, जो खरीद, इनपुट आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स के लिए साक्ष्य-आधारित योजना में सहयोग करता है। खरीफ 2025 में, तेलंगाना राज्य सहित देश भर के 604 जिलों में 28.5 करोड़ से अधिक प्लॉट्स को कवर करते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) आयोजित किया गया है।

महाराष्ट्र ने योजना कार्यान्वयन, आपदा राहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित परामर्श और ऋण पहुंच प्रदान करने के लिए एग्रीस्टैक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसमें खरीफ 2025 की फसल हानि के लिए 89 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक का अंतरण शामिल है। छत्तीसगढ़ ने एमएसपी आधारित धान खरीद के लिए किसान आईडी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण को संस्थागत रूप दिया है, जिसमें एक ही सीजन में 32 लाख से अधिक किसानों को शामिल किया गया है, जिससे पारदर्शिता, फसल सत्यापन और एमएसपी भुगतान की समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

II. कृषि निर्णय सहायता प्रणाली: कृषि निर्णयन सहायता प्रणाली एक जियो-स्पेशियल मंच है जो कृषि नियोजन और निर्णयन में सहायता के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके सेटेलाइट इमेजरी, मौसम, मिट्टी और फसल के आंकड़ों को एकीकृत करता है। यह फसल, मौसम और मिट्टी पर लक्षित परामर्श उपलब्ध कराने के लिए एक विश्लेषणात्मक मंच (वेब-पोर्टल) के रूप में कार्य करता है।

III. किसान ई-मित्र: यह एक ध्वनि-आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट है जिसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किसानों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विकसित किया गया है। यह समाधान 11 क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करता है और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सहायता के लिए विकसित हो रहा है। वर्तमान में, यह

औसतन प्रतिदिन 8,000 से अधिक किसानों के प्रश्नों का समाधान करता है और अब तक 95 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं।

IV. राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली: जलवायु परिवर्तन के कारण उपज की हानि से निपटने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, फसलों में कीट संक्रमण का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिससे स्वस्थ फसलों के लिए समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है। यह तंत्र, जिसका उपयोग वर्तमान में 10,000 से अधिक कृषि विस्तार कार्यकर्ता कर रहे हैं, किसानों को कीटों की इमेज लेने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें कीटों के संक्रमण से बचाव और फसल हानि को कम करने में सहायता मिलती है। वर्तमान में, यह 65 फसलों और 400 से अधिक कीटों को कवर करता है।

V. नमो ड्रोन दीदी: सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना 'नमो ड्रोन दीदी' को अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजना का प्रमुख उद्देश्य दक्षता में सुधार, फसल की उपज में वृद्धि और प्रचालन लागत को कम करने के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है साथ ही, एसएचजी को ड्रोन सेवा प्रदाताओं के रूप में सशक्त बनाना है ताकि उनकी आय बढ़े और आजीविका में सहायता मिल सके। प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 ड्रोन वितरित किए हैं। कृषि विकास और ग्रामीण परिवर्तन केंद्र (एडीआरटीसी), बेंगलुरु ने इन 500 ड्रोनों के संचालन की आर्थिक और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि ड्रोनों को अपनाने से एसएचजी की गतिविधियों में विविधता आई है, कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ है और ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के लिए आय के अवसर बढ़े हैं।

VI. सीड़ ऑथेंटिसिटी ट्रेसेबिलिटी एंड हॉसिस्टिक इन्वेंटेरी (साथी): यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो पूरे भारत में बीज उत्पादन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, वितरण और ट्रेसेबिलिटी के समग्र प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। इस प्रयास के तहत एक राष्ट्रीय बीज ग्रिड (एनएसजी) स्थापित किया गया है, जो सभी बीज हितधारकों को एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है।

अनुबंध

किसान रजिस्ट्री की वर्तमान स्थिति (04.02.2026 तक):

क्रं. सं.	राज्य	किसान आईडी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	4600703
2	असम	1186105
3	बिहार	3195225
4	छत्तीसगढ	3230335
5	गुजरात	5948260
6	हरियाणा	1042867
7	हिमाचल प्रदेश	529507
8	कर्नाटक	4514824
9	केरल	2249894
10	मध्य प्रदेश	10179309
11	महाराष्ट्र	13127493
12	ओडिशा	1432091
13	पंजाब	257
14	राजस्थान	8181707
15	तमिलनाडु	3294405
16	तेलंगाना	4046409
17	त्रिपुरा	59258
18	उत्तर प्रदेश	18069061
19	उत्तराखंड	26114

*****